

पायलट एसोसिएशन ने ‘‘रॉयटर’’ व ‘‘वॉल स्ट्रील जर्नल’’ को कोर्ट का नोटिस भेजा

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ संस्थानों ने एयर इंडिया की अहमदाबाद फ्लाइट के क्रैश के बारे में बिना प्रमाण के ‘‘कयासबाजी’’ के आधार पर, जो खबर प्रसारित की है, उससे भारत के ‘‘सिविल एविएशन’’ (नागरिक उड्डयन) की ‘‘सेफ्टी’’ की प्रतिष्ठा को भारी चोट पहुँची है

—सुकुमार साह—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 19 जुलाई। भारतीय पायलट संघ (फैडरेशन ऑफ इण्डियन पायलट्स/ एफ.आई.पी.) ने, गैर जिम्मेदाराना और पायलटों को छवि को नुकसान पहुँचाने वाली पत्रकारिता के खिलाफ एक असाधारण कदम उठाया है। शुरुवार को, एफ.आई.पी. ने पुष्टि की कि उसने एआई 171 विमान क्रैश पर हालिया रिपोर्टों को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटरस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पायलट संघ ने दोनों मीडिया संगठनों से सार्वजनिक माफी की भी मांग की है।

एफ.आई.पी. के अध्यक्ष कैप्टन सीदस रंभावा ने कहा, ‘‘हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटरस के खिलाफ औपचारिक नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इस प्रकार की अटकलें, विशेष रूप से बिना तथ्यों वाली, सार्वजनिक चिंता पैदा करती हैं

■ नोटिस में माँग की गई है कि रॉयटर ऐसी कयासबाजी पर आधारित खबरें छापना बंद करे तथा 17 जुलाई को जो खबर प्रकाशित की उसमें उचित परिवर्तन करके, स्थापित करे कि उसकी खबर ‘‘आधारहीन’’ थी तथा अभी ‘‘क्रैश’’ की जाँच जारी है, अतः अभी कोई निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं है।

■ अगर ‘‘रॉयटर’’ व वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये संशोधन नहीं किया तो मानहानि, मानसिक पीड़ा का मुकदमा चलाया जायेगा।

■ अमेरिका के नैशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने भी रॉयटर व वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर की काफी भर्त्सना की है।

और भारतीय विमानन की सुरक्षा के बारे में धारणा को कमजोर करती है।’’

एफ.आई.पी. ने दो वैश्विक समाचार संगठनों को भेजे गए ईमेल में उनकी रिपोर्टिंग को ‘‘अप्रमाणित तथा सिलेक्टिव’’ बताया और कहा, ‘‘ऐसी

कार्रवाइयाँ गैर-जिम्मेदार हैं, खासकर तब जबकि जाँच अभी जारी है।’’ संघ ने इन मीडिया आउटलैट्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनावश्यक डर पैदा किया और भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली को छवि को विकृत किया।

विशेष रूप से, एफ.आई.पी. ने पायलटों को उनकी मृत्यु के बाद दोषी ठहराए जाने पर गहरी चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार की अटकलें ‘‘मृत पायलटों की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान पहुँचाती हैं, जो अपनी ओर से बचाव नहीं कर सकते।’’ संघ ने तर्क दिया कि ऐसी कथार्रैन केवल शोक संतप्त परिवारों को दुख पहुँचाती हैं, बल्कि पूरे पायलट समुदाय का मनोबल भी प्रभावित करती हैं, जो भारी दबाव में काम करता है।

कानूनी नोटिस में विशेष रूप से यह मांग की गई कि रॉयटर्स भविष्य में ऐसी अटकलों से बचे और 17 जुलाई को प्रकाशित अपने लेख में संशोधन करके उसमें उपयुक्त अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) जोड़े और ऐसी किसी भी सामग्री को हटाए जिसे दोषारोपण के रूप में समझा जा सकता है। पायलट संघ ने रॉयटर्स से यह भी कहा कि वह एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपर लीक प्रकरण में डामोर को जमानत नहीं

जयपुर, 19 जुलाई। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक मामले में आरोपी विजय कुमार डामोर को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने दो अन्य मामलों को लेकर आरोपी की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्रों को भी खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपी पर पेपर लीक के कई प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

डामोर द्वारा जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह करीब ढाई साल से न्यायिक

■ आरोपी विजय कुमार डामोर पर बेकरिया व सुखेर थाने में भी पेपर लीक मामले की एफआईआर दर्ज है।

अभिरक्षा में चल रहा है। वहीं, उसके खिलाफ प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए इसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बताया कि पेपर लीक के मामले में आरोपी के खिलाफ बेकरिया और सुखेर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी भर्ती के सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न पत्र अनिल मीणा को उपलब्ध कराने के षडयंत्र में बाबूलाल कटारा के साथ लिप्त था। आरोपी ने प्रश्न पत्र को हाथ से रजिस्टर में उतारा और अनिल मीणा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उड़ान भरने से पहले ही मस्क की ‘‘अमेरिका पार्टी’’ क्रैश हो गई

सीएनएन व क्विननिपैक युनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में किये गए सर्वे के अनुसार, क्रमशः 22 प्रतिशत व 17 प्रतिशत रजिस्टर्ड मतदाता ही मस्क द्वारा तीसरी राजनीतिक पार्टी बनाने के पक्ष में हैं

—सुकुमार साह—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 19 जुलाई। जब दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति दुनिया के सबसे कठिन राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? ताजातरीन सर्वेक्षणों के अनुसार, वे रनवे पर कदम रखने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

एलन मस्क की एक नई राजनीतिक पार्टी, जिसे अस्थायी रूप से ‘‘अमेरिका पार्टी’’ कहा गया था, को स्थापित करने की योजना को उसी जनता ने खारिज कर दिया, उन्हें जिसके साथ आने की उम्मीद थी। यह विचार मस्क और उनके पूर्व सहयोगी, यूएस राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच सार्वजनिक विवाद के बाद उभरा था, और इसका उद्देश्य दो-पार्टी प्रणाली को तोड़ना था। इसके बजाय, यह विचार अमेरिकियों को ही उनके विरोध में एकजुट कर रहा है।

सीएनएन द्वारा इस सप्ताह जारी एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि

■ तथा, क्रमशः 77 प्रतिशत मतदाता मस्क द्वारा नई तीसरी पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं हैं।

■ सीएनएन के इसी सर्वे के अनुसार, 23 प्रतिशत अमेरिकी मस्क को आशा भरी आँखों से देखते हैं तथा 60 प्रतिशत अमेरिकी मस्क के बारे में नैगेटिव भावना रखते हैं, यानी मस्क की रेटिंग माइनस 37 पॉइंट है। जबकि, 2016 में मस्क की रेटिंग प्लस 29 पाइन्ट थी।

■ वैसे भी अमेरिका के इतिहास में केवल मात्र एक राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, किसी पार्टी का समर्थन प्राप्त किये बिना राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े थे और जीते थे। यह अलग बात है कि तब तक दोनों पार्टियों का अमेरिका के राजनीतिक रंगमंच पर जन्म नहीं हुआ था।

■ उसके बाद भी अमेरिका में कई बार तीसरी पार्टी के गठन का प्रयास किया गया है। जैसे, 1990 के दशक में अरबपति रॉस पैरो ने खूब पैसा हँका, पर वे सफल नहीं हुए।

केवल 25 प्रतिशत वयस्क और सिर्फ 22 प्रतिशत पंजीकृत मतदाता मस्क

द्वारा तीसरी पार्टी बनाने के विचार का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ भाजपा-आरएसएस ‘‘आप’’ के जन्मदाता हैं’

कांग्रेस के दलित नेता उदितराज ने, ‘‘आप’’ पर तीखा वार किया

—जाल खंबाता—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 19 जुलाई। आम आदमी पार्टी (आप) ने कांग्रेस-नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप अब बिहार में राजद व कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ भी चुनाव लड़ेगी।

संसद सत्र शुरू होने से महज दो दिन पहले गठबंधन में आई इस दारार पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने तीखा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘असल में आम आदमी पार्टी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का ‘‘टूल’’ है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप का जन्म भाजपा और आरएसएस की वजह से हुआ... अन्ना हजारे एक व्यक्ति थे, अरविंद केजरीवाल का एक एनबीओ था, लेकिन जिन लोगों ने पर्दे के पीछे से

■ अन्ना हजारे एक सभ्रांत व्यक्ति थे, केजरीवाल एक एनजीओ चलाते थे। भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, वी.एच.पी. व एबीवीपी ने केजरीवाल को संभावित आंदोलन व मंच दिया और इस तरह ‘‘आप’’ का जन्म हुआ।

■ संविधान को बचाने के लिए हम लोग साथ आये थे। हमारी विचारधाराएँ नहीं मिलती हैं। अतः आज उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा है, कल फिर साथ आ सकते हैं। पर, उनके जाने से इंडिया गठबंधन में कोई कमज़ोरी नहीं आई है।

इन्हें ताकत दी, वे थे भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विहिप और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी)। भाजपा ने उन्हें एक सुसज्जित आंदोलन और मंच दिया, और इसी तरह आप का जन्म हुआ। उनकी विचारधारा, भाजपा और आरएसएस की है।

उन्होंने आगे कहा: ‘‘अरविंद केजरीवाल दलित-विरोधी हैं और

सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं... हमारी विचारधाराएं कभी मेल नहीं खाईं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए हम साथ आए थे। अब यह उन पर निर्भर है कि वे गठबंधन में रहना चाहते हैं या नहीं... हो सकता है कि वे फिर से बाहर से भाजपा की मदद करें। वे भविष्य में फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक यात्री से 4 किलो कोकीन मिली

नयी दिल्ली, 19 जुलाई। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री से चार किलोग्राम से अधिक कोकीन जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये है। इस प्रकरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

चित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञापन के

■ कोकीन कॉमिक्स में छुपाकर रखी गई थी। इसकी कीमत 40 करोड़ के लगभग बताई जा रही है।

अनुसार, एक विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की बेंगलुरु क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने शुक्रवार को सुबह दोहा से बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुँचे एक भारतीय पुरुष यात्री को रोका। उसके सामान की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर पता चला कि उसके पास दो सुपरहीरो कॉमिक्स और पत्रिकाएँ थीं, जो असामान्य रूप से भारी थीं। अधिकारियों ने पत्रिकाओं के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईंडी ने उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ती रावत तथा इन दोनों के सहयोगी बीरेन्द्र सिंह कंडारी, लक्ष्मी सिंह राणा व दिवंगत सुशीला रानी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने दो भूखंड, जिनका क्षेत्रफल 101 बीघा था, बहुत कम दामों में बेच कर ‘‘मनी लॉण्डरिंग’’ का अपराध किया?

—जाल खंबाता—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 19 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट-ईडी) ने शुक्रवार (19 जुलाई, 2025) को कहा कि उसने उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉण्डिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला देहरादून में दो भूखंडों को, कथित रूप से, हड़पने से जुड़ा है, जिनकी बाजार कीमत 70 करोड़ रूपए से अधिक बताई जा रही है।

केन्द्रीय जाँच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कम्प्लेंट) राज्य की राजधानी देहरादून की एक विशेष

■ ईडी के अनुसार, इन दो भूखंडों की कीमत बाज़ार में 70 करोड़ रूपए बताई गई है।

■ हरक सिंह रावत उत्तराखंड में ‘‘वन मंत्री’’ थे तथा 2022 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे।

प्रिवेन्शान ऑफ मनीलॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) में दर्ज की गई है। चार्जशीट में जिन आरोपियों के नाम हैं, उनमें हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत, उनके कथित सहयोगी बीरेन्द्र सिंह कंडारी, लक्ष्मी सिंह राणा और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट शामिल हैं।

हरक सिंह रावत (64) उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से

इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा था।

ईडी का यह पीएमएलए केस उत्तराखंड पुलिस की उस प्राथमिकी पर आधारित है, जो दीप्ति रावत और लक्ष्मी सिंह राणा के खिलाफ दर्ज की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने बीरेन्द्र सिंह कंडारी, हरक सिंह रावत, स्व. सुशीला रानी और कुछ अन्य लोगों द्वारा की गई एक ‘‘साजिश’’ के तहत, इस जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई।

ईडी ने कहा, ‘‘माननीय न्यायालय

के स्पष्ट आदेश के बावजूद, सुशीला रानी ने अन्य लोगों के साथ साजिश रचकर, सहसपुर, देहरादून स्थित इन जमीनों की दो पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत करवाई।

‘‘इन भूखंडों को पावर ऑफ अटॉर्नी धारक बीरेन्द्र सिंह कंडारी, जो हरक सिंह रावत के करीबी माने जाते हैं, ने दीप्ति रावत और लक्ष्मी सिंह राणा को उस क्षेत्र में प्रचलित सर्किल रेट से काफी कम कीमत पर बेचा।’’

ईडी ने आगे बताया कि दीप्ति रावत द्वारा खरीदे गए ये भूखंड अब ‘‘दून इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज’’ का हिस्सा हैं, जिसे ‘‘हरक सिंह रावत के परिवार और दोस्तों द्वारा ‘‘नियंत्रित’’ श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्वर्ण मंदिर को आठवीं बार बम से उड़ाने की धमकी

अमृतसर, 19 जुलाई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को शनिवार को स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक और ई-मेल मिला। चौदह जुलाई के बाद से यह ऐसी आठवीं ऐसी धमकी है।

ऐसी धमकियों के मद्देनजर, पवित्र सिख तीर्थस्थल स्वर्ण मंदिर के आसपास

■ शनिवार को भी ईमेल भेजकर धमकी दी गई। इस मामले में गिरफ्तार शुभम दुबे से पूछताछ चल रही है।

सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। मंदिर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी अश्रिय घटना को रोकने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी परिसर में गश्त कर रहे हैं। अकाल तख्त के कार्यवाहक जयेंदर ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने अब तक अपराधियों की पहचान करने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बघेल छत्तीसगढ़ के जंगल अडानी को देने का विरोध कर रहे हैं इसलिए उन पर यह कार्यवाही की गई है, पर हम डरने वाले नहीं हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनके परिवार को इसकी सजा दी जा रही है। वाड़ा ने आज यहां कहा कि बघेल इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाले थे लेकिन उससे पहले ही उनकी आवाज (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ग्राउन्ड ब्रेकिंग लक्ष्य हासिल करने के लिए ऊर्जा, उद्योग, खनन, यूडीएच, कृषि तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की सराहना की।

अवसर भी सृजित हो रहे हैं। शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एसओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश

दिए कि आपसी समन्वय से एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही, आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करें।

उन्होंने उद्योग विभाग को सभी विभागों से समन्वय कर एमओयू



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एसओयू क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया में और तेजी लाएं।